# गबन की धनराशि माफ करने की तैयारी

**फ़रीदाबाद ( मज़दूर मोर्चा )** भ्रष्टाचार का गढ़ बनती जा रही रेडक्रॉस सोसायटी में भ्रष्टाचारियों को न सिर्फ संरक्षण देकर आगे बढ़ाया जा रहा है उनके गबन को भी छिपाने के तरीके निकाले जा रहे हैं। वर्तमान में गुड़गांव में तैनात साठ हजार रुपये गबन के आरोपी जितेन शर्मा की यह राशि माफ करने की तैयारी की जा रही है।

वर्ष 2019 में फरीदाबाद रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से दो दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था। इसके अभ्यर्थियों से सहयोग राशि वसूलने के लिए जितेन शर्मा को सोसायटी की ओर से साठ हजार रुपये कीमत की दो रसीद बुक जारी की गई थीं। जितेन ने ट्रेनिंग तो करा दी लेकिन अभ्यर्थियों से वसूला गया साठ हजार रुपया सोसायटी के अकाउंट में नहीं जमा करवाया था। यह गबन ऑडिट में पकड़ में आया और ऑडिटर ने रकम की वसूली किए जाने की सिफारिश की।

होना तो यह चाहिए था कि गबन पकड़े जाने के बाद जितेन से रकम की वसूली की जाती। इसके विपरीत जितेन से लिखवा लिया गया कि वह दो रसीद बुकें कहीं गुम हो गईं। पक्का करने के लिए जितेन ने घटना के दो साल बाद और ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद रसीद बुकें गुम होने का रपट रोजनामचा सेंट्रल थाने में दर्ज करा दी।

रेडक्रॉस सोसायटी के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार अब जितेन शर्मा ने महासचिव मुकेश अग्रवाल और वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता को पत्र लिख कर गबन की यह राशि माफ किए जाने की मांग की है। सोसायटी के सदस्य और कर्मचारियों में चर्चा है कि जितेन को बचाने के लिए यह रास्ता ऊपर के ही लोगों ने उसे सुझाया, अब उसके पत्र के आधार पर यह राशि माफ करने की भूमिका बनाई जा सकती है। इन लोगों का कहना है कि रसीद बुकें रेडक्रॉस सोसायटी की यानी सरकारी हैं न कि जितेन शर्मा की। वसूले गए साठ हजार रुपये रेडक्रॉस सोसायटी की अमानत हैं, या तो रुपयों की रिकवरी हो या फिर रसीद बुकें लौटाई जाएं, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जितेन को रेडक्रॉस ने कोई कर्ज नहीं दिया था जिसे माफ किया जाए, यह तो वसूली गई राशि की बात है जो खजाने में जरूर जमा कराई जानी चाहिए। यदि यह धनराशि माफ कर दी जाती है तो भविष्य में इस तरह के गबन और बढ़ने की संभावना है क्योंकि सदस्य, कर्मचारियों को लगेगा कि खो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद राशि माफ कराई जा सकती है।

# दागी विमल खंडेलवाल की तैनाती से असंतुष्ट स्टेट मेंबर ने इस्तीफे की पेशकश की

**फ़रीदाबाद ( मज़दूर मोर्चा )** कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे लोगों के तीमारदारों से दस दस हज़ार रुपये ऐंठने के आरोपी विमल खंडेलवाल को स्टेट सब कमेटी में सदस्यता दिए जाने का विरोध रेडक्रॉस सोसायटी में बढ़ने लगा है। दागियों को बढ़ावा देने से परेशान स्टेट कमेटी के मेंबर मनोज बंसल ने सचिव को इस्तीफा भेज दिया। हालांकि महासचिव मुकेश अग्रवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर जल्द ही बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है।

समाज सेवी संस्था रेडक्रॉस सोसायटी भी अब भाजपा, संघ और उनके सहयोगी संगठनों से जुड़े लोगों के घुसने के कारण भ्रष्टाचार का गढ़ बनती जा रही है। इन संगठनों से आए सदस्य भ्रष्टाचार करते हैं और ऊंचे पद पर बैठाए गए भाजपाई उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन सिलिंडर की अवैध रूप से सिक्योरिटी वसूलने के आरोपी विमल खंडेलवाल को राज्यपाल ने एक सब कमेटी का सदस्य बना दिया। विजिलेंस जांच झेल रहे दागी विमल खंडेलवाल को स्टेट सब कमेटी का सदस्य बनाए जाने से रेडक्रॉस स्टेट कमेटी के सदस्यों में रोष व्याप्त है।

मनोज बंसल

सोसायटी के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार विमख खंडेलवाल की पदोन्नति से आहत स्टेट रेडक्रॉस सोसायटी के सदस्य मनोज बंसल ने 10 अगस्त को वाट्सएप पर अपना इस्तीफा महासचिव मुकेश अग्रवाल और वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता को भेज दिया। इस्तीफे का कारण बताया कि धूमिल छवि के लोगों को सोसायटी में बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार में व्याप्त कर्मचारियों को संरक्षण देने और (घोटालों की) निष्पक्ष जांच न होने के कारण दुखी होकर अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं।

विमल खंडेलवाल को बढ़ावा देने से सिर्फ मनोज बंसल ही नहीं दुखी हैं सोसायटी के बहुत से अन्य सदस्यों में भी रोष व्याप्त है। इन लोगों में चर्चा है कि भ्रष्टाचारी विमल खंडेलवाल को पेट्रन बनाया गया है। जब सोसायटी की लुटिया ही डुबोनी है तो बाकी के 11 पैट्रन को भी भ्रष्टाचार की छूट दे दो।

चर्चा यह भी है कि राज्यपाल से लेकर महासचिव तक सब भाजपाई पृष्ठभूमि से हैं। ऐसे में ऑक्सीजन घोटाले के मुख्य आरोपी विमल खंडेलवाल या तत्कालीन सचिव विकास और सहभागी जितेन के खिलाफ शायद ही कोई कार्रवाई होगी, जिस तरह ऑक्सीजन घोटाले की विजिलेंस जांच पेंडिंग पड़ी है उसी तर्ज पर इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर इन्हें बढ़ावा दिया जाता रहेगा।

सूत्र बताते हैं कि महासचिव ने मनोज बंसल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। मुकेश अग्रवाल और सुषमा गुप्ता अब फरीदाबाद आकर इस मामले पर मनोज बंसल से सीधे बातचीत करेंगे, इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मनोज बंसल से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका।

# हाजी जमात अली के पशु-धन लूट मामले की अपडेट

हाजी जमात अली

**क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा**

**खोरी ज़मालपुर, तहसील धौज़, ज़िला फ़रीदाबाद निवासी, ग़रीब किसान व पशुपालक, हाजी ज़मात अली की 56 गायें, 8 बछड़े, 17 बकरियां और 4 गधे; 30 जून को गुंडे-दंगाई, बिट्टू बजरंगी और उसके गुंडा-गिरोह ने लूट लिए थे. वे हथियार लहराते हुए, कई गावों से गुजरे थे, उनके ख़िलाफ़ लूट के मामले की एफ़आईआर, धौज पुलिस स्टेशन में दर्ज है. इस भयानक लूट की वारदात का पता लगने पर, 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' की एक 4 सदस्यीय टीम, 4 जुलाई को पीड़ित परिवार से मिलने, स्थिति की सही जानकारी करने, वहां गई थी. पूरी रिपोर्ट 'मज़दूर मोर्चा' साप्ताहिक ने कवर की थी. उसी घटना की और आगे तफ्शील करने और लूट की इस वारदात पर सख्त कार्यवाही कराने व पशु-धन वापस कराने की मंशा से एक 3 सदस्यीय टीम, 'वर्कर्स यूनिटी पोर्टल' एवं 'मज़दूर समाचार' चेनल की टीम के साथ दोबारा भी खोरी ज़मालपुर, बाईखेड़ा गांव जहाँ लुटी गई गायों में से 2 मौजूद थीं, निमोठ पुलिस चौकी जहाँ लुटेरों ने पीड़ित ज़मात अली के विरुद्ध ही एफआईआर कराई हुई थी, तथा धौज़ पुलिस स्टेशन गई थी. उसे लगातार फॉलो अप किया गया था.**

**हाजी ज़मात अली के परिवार से इस घटना का मिला अपडेट यह है, कि उनका लुटा सारा पशु-धन उन्हें 8 अगस्त को वापस मिल गया है तथा उनके विरुद्ध दायर एफआईआर निरस्त हो चुकी है. गधे तो इतने समझदार निकले कि बिना पुलिस कार्यवाही और कोर्ट कचहरी का इंतज़ार किए, एक सप्ताह बाद ही अपने आप, अपने सही ठिकाने पर पहुँच गए थे. बाक़ी पशु भी उन्हें सही-सलामत वापस मिल गए. किसी को चराई के नाम पर भी कोई भुगतान नहीं करना पड़ा. हाजी ज़मात अली के भतीजे ने खुशी के साथ यह जानकारी देते हुए, अपने पूरे परिवार की तरफ से, 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' का तहे दिल से धन्यवाद किया और संगठन से हमेशा के लिए जुड़ने की इच्छा व्यक्त की. साथ ही, उन्होंने अपने पूरे परिवार की ओर से, फ़रीदाबाद से प्रकाशित, प्रतिष्ठित साप्ताहिक 'मज़दूर मोर्चा' और पोर्टल 'वर्कर्स यूनिटी' तथा 'मज़दूर समाचार' चेनल का भी तहे दिल से धन्यवाद अदा किया.**

# कुत्तों की नसबंदी पर खर्च किए 1.36 करोड़ रुपये, बीस फीसदी बढ़ी कुत्तों की संख्या

## नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने एनजीओ की मिलीभगत से लूटा जनता का पैसा

**फ़रीदाबाद ( मज़दूर मोर्चा )** भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुके नगर निगम के अधिकारी सरकारी खजाने को हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुत्तों की नसबंदी के नाम पर एनजीओ पीपुल्स फॉर एनिमल फरीदाबाद यूनिट-II के साथ लगभग 1.36 करोड़ रुपये की बंदरबांट की गई। इतनी राशि खर्च किए जाने के बावजूद कुत्तों की जनसंख्या में 20 फीसदी का इज़ाफा हुआ जो घोटाले की पुष्टि करता है।

आवारा कुत्तों की देखभाल की मद नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की लूट कमाई का बढ़िया औज़ार साबित हुई। निगम अधिकारी प्रीति दुबे की एनजीओ को कुत्तों की देखरेख, टीका लगाने और नसबंदी कराने के नाम पर करोड़ों रुपये लुटाते रहे। काग़ज़ों पर हवा-हवाई रिकॉर्ड बना कर खेल किया गया। आरटीआई में जानकारी मांगी गई तो अधिकारियों ने आधे-अधूरे हवा-हवाई आंकड़े पेश कर दिए, जिनसे इसका खुलासा हुआ।

आरटीआई कार्यकर्ता रवींद्र चावला की कुत्तों से संबंधित आरटीआई का जवाब निगम अधिकारियों ने पहली अपील लगाए जाने पर ही दिया। 2019 से 2021 तक शहर में आवारा कुत्तों की संख्या के सवाल पर बताया गया कि लगभग 42,421 थी। कुत्तों की यह गणना कैसे की गई थी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। लगभग में कुत्तों की संख्या बताया जाने से लगता है कि यह संख्या कार्यालय में ही बैठे बैठे तय कर दी गई थी।

बताया गया कि 2019 से 2023 के बीच कुत्तों की नसबंदी के लिए निगम ने प्रीति दुबे की एनजीओ को 1,35,80,450 रुपयों का भुगतान किया। कुत्तों की नसबंदी के लिए नगर निगम ने उनकी एनजीओ को जगह भी मुहैया कराई। 2019 में जिन कुत्तों की संख्या 42421 थी उनकी संख्या 2023 में लगभग बीस प्रतिशत बढ़ कर 52650 हो गई। सवाल है कि जब कुत्तों की नसबंदी की गई तो फिर उनकी संख्या बढती क्यों गई, उस पर नियंत्रण क्यों नहीं हुआ?

नगर निगम ने प्रीति दुबे को कुत्तों की नसबंदी के लिए कहां जगह मुहैया करवाई है इसकी जानकारी नहीं दी गई। मज़दूर मोर्चा ने भी उस जगह को तलाशने का काफी प्रयास किया लेकिन वह हो तभी तो मिलेगी। यह बताते चलें कि प्रीति दुबे पशु प्रेमी हैं लेकिन पशु चिकित्सक नहीं, न ही उनकी एनजीओ में कोई पशु चिकित्सक है। ऐसे में कुत्तों की नसबंदी किससे करवाई गई यह बड़ा सवाल है। दरअसल, न तो नगर निगम और न ही प्रीति दुबे ने कभी कुत्तों की गणना की। सड़क पर बीमार, आवारा या घायल कुत्ता मिलने की सूचना पर उसे उठा कर सोशल मीडिया पर प्रचारित करने के अलावा कोई ठोस काम किया ही नहीं गया।

यह भ्रष्टाचार का द्योतक है कि प्रीति दुबे सोशल मीडिया पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की फोटो वीडियो डालती हैं और नगर निगम आरटीआई में जानकारी देता है कि शहर में एक भी डॉग पाउंड नहीं है। यानी वह जगह जहां आवारा, बीमार, घायल कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ज़ाहिर है कि चंद कुत्तों को दाना डाल कर निगम अधिकारी और एनजीओ के पदाधिकारी बड़े पैमाने पर कुत्ता कल्याण करने का पाठ पढ़ा कर करोड़ों रुपये डकारते रहे। रवींद्र चावला कहते हैं कि मामले की विजिलेंस से जांच कराई जाए तो नगर निगम में कुत्तों के नाम पर बीते नौ साल में करोड़ों रुपयों के घोटाले का खुलासा होगा।